भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

10.03.2021 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2632 का उत्तर

भारतीय राष्ट्रीय रेल योजना-2030

2632. श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):
डॉ. जयंत कुमार राय:
श्री भोला सिंह:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:
श्री विनोद कुमार सोनकर:
कुमारी शोभा कारान्दलाजे:
श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी:
श्री वी. के. श्रीकंदन:
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे ने वर्ष 2030 तक 'फ्यूचर रेडी' रेलवे प्रणाली के निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्रीय रेल योजना-2030 तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का इसकी शुरुआत के बाद प्रचालन और अनुरक्षण के लिए इसका अवसंरचना सम्बन्धी परिसंपत्तियों और समर्पित माल वहन गलियारा (डीएफसी) संबंधी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने वर्ष 2024 तक कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए विज़न 2024 शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) नई डीएफसी को कब तक शुरू किये जाने का अनुमान है और 31 दिसम्बर 2020 के अनुसार इस अवसंरचना परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित और खर्च की गई है;

(च) क्या सरकार ने मेट्रो रेल प्रणाली की लागत में कमी करने के लिए दो नई प्रौद्योगिकियां 'मेट्रोलाइट' और 'मेट्रोनियो' शुरू करने का प्रस्ताव दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) देश में रेलवे में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

रेल, वाणिज्य एवं उद्योग और

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (छ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

sk

भारतीय राष्ट्रीय रेल योजना-2030 के संबंध में दिनांक 10.03.2021 को लोक सभा में श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या), डॉ. जयंत कुमार राय, श्री भोला सिंह, श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव, डॉ. सुकान्त मजूमदार, श्री विनोद कुमार सोनकर, कुमारी शोभा कारान्दलाजे, श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी, श्री वी. के. श्रीकंदन और श्री राजा अमरेश्वर नाईक के अतारांकित प्रश्न सं. 2630 के भाग (क) से (छ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): भारतीय रेल ने भारत के लिए राष्ट्रीय रेल योजना-2030 तैयार की है। 2030 तक 'भविष्य के लिए तैयार' रेलवे प्रणाली तैयार करने की योजना है। राष्ट्रीय रेल योजना का लक्ष्य माल ढुलाई में रेलवे की मोडल हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ाने के लिए परिचालनिक क्षमताओं और वाणिज्यिक नीतिगत पहलों दोनों के आधार पर रणनीतियां तैयार करना है। इस योजना का उद्देश्य मांग से पहले क्षमता का सृजन करना है, जिसके परिणामस्वरूप 2050 तक भविष्य की मांग को पूरा भी किया जा सकेगा और माल यातायात में रेलवे की निश्चित हिस्सेदारी 45% तक बढ़ेगी। योजना के मसौदे को पब्लिक डोमेन (भारतीय रेल की वेबसाइट) में रखा गया है और इसे टिप्पणियों/राय के लिए हितधारकों के बीच परिपत्रित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय रेल योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं:-

• माल ढुलाई में रेलवे की मोडल हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ाने के लिए परिचालनिक क्षमताओं और वाणिज्यिक नीतिगत पहलों दोनों के आधार पर रणनीतियां तैयार करना।

• माल गाड़ियों की औसत गति को बढ़ाकर 50 किमी प्रति घंटा करने से माल ढुलाई के पारगमन समय को काफी कम करना।

• राष्ट्रीय रेल योजना के भाग के रूप में, 2024 तक 100% विद्युतीकरण, भीड़भाड़ वाले मार्गों को मल्टी ट्रैक करना, दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई मार्गों पर 160 किमी प्रति घंटे तक गति का उन्नयन, अन्य सभी स्वर्णिम चतुर्भुज-स्वर्णिम विकर्ण (जीक्यू/जीडी) मार्गों पर 130 किमी प्रति घंटे तक गति का उन्नयन और सभी जीक्यू/जीडी मार्ग पर सभी समपारों को समाप्त करना जैसी कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए विजन 2024 शुरू किया गया है।

•नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की पहचान करना।

• नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की पहचान करना।

• यात्री यातायात के लिए चल स्टॉक की आवश्यकता के साथ-साथ माल ढुलाई के लिए माल डिब्बों की आवश्यकता का आकलन करना।

• 100% विद्युतीकरण (हरित ऊर्जा) और माल ढुलाई में मोडल शेयर बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लोकोमोटिव की आवश्यकता का आकलन करना।

• पूंजी में कुल निवेश का आकलन करना जो आवधिक विवरण के साथ अपेक्षित होगा।

• चल स्टॉक के संचालन और स्वामित्व, माल ढुलाई और यात्री टर्मिनलों के विकास, रेलपथ अवसंरचना के विकास/संचालन आदि जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की निरंतर भागीदारी।

(ग): जी हां। 2020-21 के बजट भाषण में इसकी घोषणा की गई है, {पैरा 47 (ख) और 47 (घ) v)}। अभी तक, जानकारी पर काम नहीं किया गया है।

(घ) जी हां। 3750 किलोमीटर की कुल लंबाई की 58 अति महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिनकी लागत 39,663 करोड़ रुपये है, जिसमें से, 2279 किलोमीटर लंबाई को चालू कर दिया गया है और मार्च 2020 तक 28,891 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। इसी प्रकार, 6913 किलोमीटर की कुल लम्बाई की 68 महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिनकी लागत 75,736 करोड़ रुपये है, जिसमें से 838 किलोमीटर लंबाई को चालू कर दिया गया है और मार्च, 2020 तक 25,434 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। अब तक, 25 अति महत्वपूर्ण परियोजनाएं और 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

(ङ) निम्नलिखित डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने से संबंधित कार्य डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सौंपा गया है:-

(i) ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर- खड़गपुर- विजयवाड़ा- लंबाई 1115 किलोमीटर

(ii) ईस्ट-वेस्ट सब कॉरिडोर

क. भुसावल-वर्धा-नागपुर-राजखारसवान-खड़गपुर-उलुबेरिया-दानकुनी-लंबाई-1673 किलोमीटर

ख. राजखरसवान-कालीपहाड़ी-अंदल- 195 किलोमीटर

(iii) नॉर्थ साउथ सब कॉरिडोर- विजयवाड़ा -नागपुर-इटारसी - लंबाई - 975 किलोमीटर

नए डीएफसी को शुरू करने और कार्यान्वयन और वित्तपोषण के तरीके के संबंध में निर्णय डीपीआर के अंतिम परिणाम पर आधारित होता है।

(च) शहरी परिवहन शहरी विकास का अभिन्न अंग है जो राज्य का विषय है। इसलिए, संबंधित राज्य सरकारें शहरों या शहरी संकुलों में मेट्रो रेल परियोजनाओं/मेट्रोलाइट/मेट्रोनियो सहित शहरी परिवहन अवसंरचना को शुरू करने और विकसित करने के लिए जिम्मेदार हैं। जब कभी राज्य सरकारों द्वारा प्रस्ताव किये जाते हैं, केंद्र सरकार प्रस्ताव की व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर मेट्रो

रेल प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता देने के बारे में विचार करती है। नई प्रौद्योगिकियों को ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(i) मेट्रोलाइट - आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जुलाई, 2019 में "मेट्रोलाइट" नामक लाइट अर्बन रेल ट्रांजिट सिस्टम के मानक जारी किए गए हैं। यह कम लागत वाला समाधान कम यात्रियों वाले शहरों के लिए उपयुक्त है जो रेल-आधारित मास ट्रांजिट सिस्टम के इच्छुक हैं। इस प्रणाली को उच्च क्षमता वाली मेट्रो रेल प्रणाली के लिए फीडर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे मेट्रोलाइट को छोटे शहरों में मास ट्रांजिट के प्रमुख तरीके के रूप में अपनाएं। इसके निर्माण की लागत उच्च क्षमता वाली मेट्रो प्रणाली का लगभग 40% है। यह प्रणाली अपनी बहुत कम पूंजी, परिचालन और अनुरक्षण लागत के कारण अधिक व्यवहार्य और टिकाऊ है।

(ii) मेट्रोनियो- मेट्रोनियो रबर-टायर वाला इलेक्ट्रिक कोच है जो एक अनन्य मार्गाधिकार के साथ रोड स्लैब पर चलने वाले ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम द्वारा संचालित है, जिसकी मानक विशिष्टि आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा नवंबर 2020 में जारी की गई है। यह एक पारंपरिक मेट्रो प्रणाली की तरह आराम, सुविधा, संरक्षा, समयबद्धता, विश्वसनीयता और पर्यावरण अनुकूलता के मामले में एक समान अनुभव और यात्रा में आसानी प्रदान करेगा। यह लोअर पीक आवर पीक डायरेक्शन ट्रैफिक (पीएचपीडीटी) के साथ टियर-2 शहरों के लिए उपयुक्त है। मेट्रोनियो की कम पूंजीगत लागत के लिए कम एक्सल लोड (10 टन) के कारण बहुत हल्की सिविल संरचना, ट्रैक की अनुपस्थिति और संचार आधारित गाड़ी नियंत्रण (सीबीटीसी) सिगनलिंग, ओपन और सिंपल स्टेशन संरचना, मेट्रोलाइट जैसे कम बिजली खपत वाले विद्युत उपकरणों की आवश्यकता जिम्मेदार हैं। इस प्रणाली को या तो एट-ग्रेड या कम कर्व रेडियस के साथ एलीवेटेड भी विकसित किया जा सकता है, इस प्रकार, भूमिगत निर्माण की आवश्यकता से बचा जा सकता है।

(छ): देश में रेलवे में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम निम्नानुसार हैं-

• परियोजना के निष्पादन में सुधार के लिए प्रक्रियागत सुधार- माल ढुलाई की दृष्टि से परियोजनाओं को अति महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण के रूप में प्राथमिकता दी गई है और इन्हें समय पर पूरा करने के लिए प्राथमिकीकृत निधि आवंटन की व्यवस्था की गई है।

• दमदार वैल्यू-फॉर-मनी लॉजिस्टिक्स समाधान प्रदान करके नए व्यवसाय को आकर्षित करने के लिए व्यापार विकास इकाइयां (बीडीयू) स्थापित की गई हैं।

• भारतीय रेल समग्र सेवा गुणवत्ता और परिचालनिक दक्षता बढ़ाने के लिए यात्री गाड़ी परिचालन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को अपना रही है।

• स्वदेश में विकसित स्वचालित गाड़ी सुरक्षा प्रणाली का प्रसार करना जो मानवीय त्रुटि के कारण गाड़ी की टक्कर को समाप्त करता है।

• भारतीय रेल ने ग्राहकों की संतुष्टि और पहुंच बढ़ाने के लिए कामकाज के सभी पहलुओं में पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों का दोहन किया है।

• एकीकृत मल्टी मॉडल समाधान- सभी साधनों में परिवहन संबंधी अवसंरचना की आद्योपांत योजना प्रदान करने के लिए, भारतीय रेल क्षेत्रीय समूह का हिस्सा है जिसमें नागरिक उड्डयन (संयोजक), पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग, आवासन और शहरी मामलों जैसे अवसंरचना संबंधी मंत्रालय शामिल हैं।

****

sk